• एचआरटीसी...

रियायती कार्ड महंगे

शिमला : हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपनी रियायती कार्ड की योजना को महंगा कर दिया है। अब निगम के रियायती कार्ड पहले से ज्यादा महंगे मिलेंगे। अपनी खस्ता वित्तीय स्थिति में सुधार करने के चलते उसने कुछ नए कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। इसमें सबसे पहले फैसला लोगों को दिए जाने वाले रियायती कार्ड को महंगा करके लिया गया है। एचआरटीसी प्रबंधन ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए सभी तरह के कार्ड महंगे करने के साथ उनकी अवधि को भी काम करने के आदेश दिए हैं। एचआरटीसी के ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और सम्मान कार्ड 50 के बजाय 100 रुपए में मिलेंगे। पहले यह कार्ड दो साल की अवधि के लिए बनाए जाते थे, जिसे कम करके अब एक साल की अवधि का कर दिया गया है।

इससे हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में यात्रा करने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। पिछले कई साल से एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपनी बसों में सफर करने के एवरेज में रियायती दरों का लाभ दे रहा है। इन रियायती कार्ड को बनवाने वाले लोगों को अपनी यात्रा के दौरान टिकट मे 25 से 30 फीसदी की छूट मिलती है। इसका सबसे अधिक फायदा रोजाना एक जगह से दूसरी जगह को सफर करने वाले लोगों को रहता है, जिनको किराए में छूट का लाभ दिया जाता है। रोजमर्रा सफर करने वालों को अब महंगी दरों पर यह कार्ड मिलेंगे जिससे उनका अपना बजट खराब हो सकता है लेकिन एचआरटीसी प्रबंधन को इससे यकीनन कुछ हद तक लाभ जरूर मिलेगा।

एचआरटीसी को हर महीने नुकसान उठाना पड़ रहा है। हर महीने उसे करीब 10 करोड़ का घाटा हो रहा है जो सालाना 120 करोड़ हो जाता है।

ग्रीन पर 25, स्मार्ट कार्ड पर दस फीसदी है छूट-एचआरटीसी के ग्रीन कार्ड पर लोगों को 25 फीसदी की छूट सफर करने पर मिलती है। वहीं स्मार्ट कार्ड पर यह छूट 10 फीसदी की रहती है, जबकि सम्मान कार्ड पर छूट 30 फीसदी की है। इसमें दूरी का फार्मूला भी है। किसी कार्ड पर 40 किलोमीटर, तो किसी में 70 किलोमीटर की दूरी पर छूट रखी गई है।

• कैबिनेट फैसले...

विभिन्न विभागों में भरेंगे 419 पद

शिमला : सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से वर्क इंस्पेक्टर के 116 पदों समेत विभिन्न विभागों में 419 पद भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में लोक निर्माण विभाग में जूनियर तकनीशियन यानी वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद भरने का फैसला हुआ। सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 21 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कांग ?ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग वृत्त खोलने और ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग मंडल खोलने सहित विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का मंडल और परवाणू में जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल खोलने सहित 17 पदों को सृजित करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। सुबाथू उपमंडल के क्षेत्राधिकार को अर्की मंडल से धर्मपुर मंडल में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला ऊना के गगरेट और अंब विद्युत मंडलों को पुनर्गठित कर हरोली में विद्युत मंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर में खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने और आवश्यक पदों का सृजन कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। लोगों की सुविधा के लिए परागपुर, नगरोटा सूरियां एवं देहरा विकास खंडों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया।

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीकृति दी। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारी के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय हुआ। जिला कांगड़ा के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कॉर्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में योगा इंस्ट्रक्टर के 6 पद भरने का निर्णय लिया गया। जिला कांगड़ा के सुरानी विकास खंड में विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा शिमला-धर्मशाला-शिमला में सप्ताह में सात दिन के बीच उड़ानों के संचालन के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के पक्ष में समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दी।

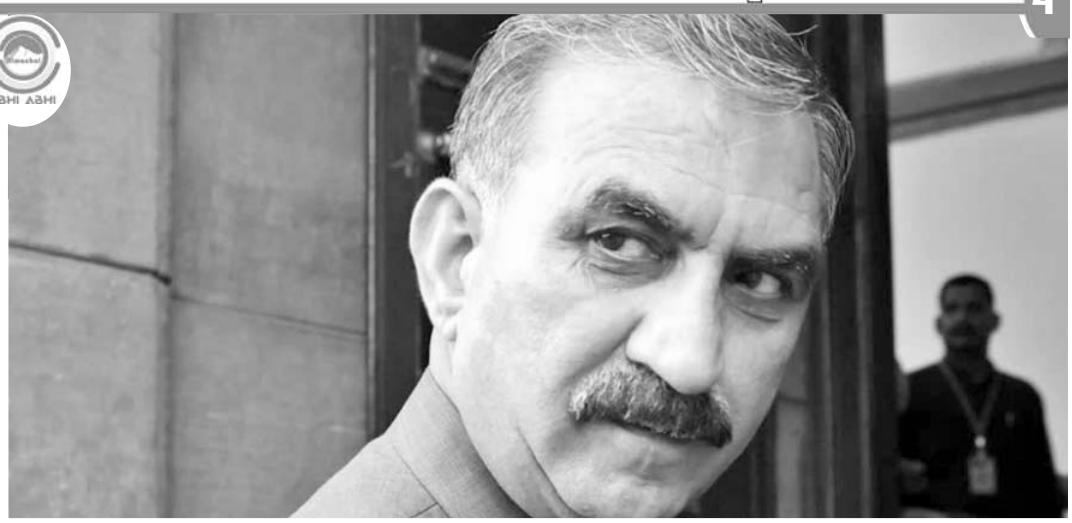

पटवारी-कानूनगो के प्रदर्शन पर सरकार सख्त

अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ओंकार शर्मा ने गुरुवार को सभी डीसी को पटवारी-कानूनगो के प्रदर्शन के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार के अनुसार पटवारी-कानूनगो का बंद करने का कृत्य स्पष्ट रूप से सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है और सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 का उल्लंघन है, जिसका उल्लंघन उन्हें उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाता है...

• संजू/ शिमला

हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानूनगो ने स्टेट कैडर और दूसरी मांगों को लेकर ऑनलाइन काम बंद कर दिया है। इससे प्रदेश के जनता रोजाना परेशान हो रही है। पटवारी और कानूनगो संघ ने गुरुवार को मांगों पर निर्णय नहीं होने के चलते अतिरिक्त कार्यभार देख रहे सर्किल की चाबियां तहसीलदार को सौंपना शुरू कर दी है। हमीरपुर व पांगी में अतिरिक्त कार्यभार की चाबियां तहसीलदार को सौंपी गई। उधर, सरकार ने अब इस मामले को गंभीरता से लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ओंकार शर्मा ने गुरुवार को सभी डीसी को पटवारी-कानूनगो के प्रदर्शन के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार के अनुसार पटवारी-कानूनगो का बंद करने का कृत्य स्पष्ट रूप से सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है और सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 का उल्लंघन है, जिसका उल्लंघन उन्हें उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाता है। यदि उन्हें सरकार के किसी फैसले से कोई शिकायत है तो बातचीत का सहारा लेना चाहिए और ऐसे कार्यों से बचना चाहिए।

सभी डीसी को निर्देश दिए हैं कि उनके नियंत्रण में काम करने वाले ऐसे सभी पटवारियों-कानूनगो को ऑनलाइन कार्यों को तुरंत फिर से शुरू करने के लिए एक सख्त सलाह जारी की जाए ताकि आम जनता को इस आधार पर अधिक परेशानी न हो। उन्हें आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में वापस शामिल होने और अतिरिक्त शुल्क सहित उन्हें दी गई अन्य जिम्मेदारियां निभाने के लिए भी कहा जाना चाहिए। यदि वे दो दिनों के भीतर इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। साथ ही जब से उन्होंने ऑनलाइन काम छोड़ा है, उस अवधि से लेकर आज तक की उनकी सेवाओं को सेवा में ब्रेक के साथ 'डाइस-नॉन' माना जाएगा। इसके अलावा यदि वे सरकारी आदेशों की अवहेलना करना जारी रखते हैं तो उनके खिलाफ निलंबन सहित अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

निर्देशों में कहा गया है कि सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। सरकार उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। हालांकि, किसी भी सरकारी कर्मचारी की ओर से कोई भी कार्रवाई जो हिमाचल प्रदेश की आम जनता के हितों के खिलाफ है, सरकार को स्वीकार्य नहीं है।

सेब पर सियासत

शिमला : हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश सरकार के फैसले के बाद इस साल सेब यूनिवर्सल कॉटन में फल मंडी पहुंच रहा है। लेकिन सिंगल लेयर यूनिवर्सल कार्टन डब्बे की क्वालिटी बागबानों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। इसी बीच अब इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने वामपंथी मित्रों के दबाव में आकर जल्दबाजी में यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का फैसला ले लिया। जिसका नुकसान अब बागवानों को झेलना पड़ रहा है। साथ ही टेलिस्कोपिक कार्टन के पूरी तरह बैन पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। साथ ही बीजेपी ने इस साल बागवानों को टेलिस्कोपिक कार्टन के इस्तेमाल पर रिलैक्सेशन देने की भी मांग की है। बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस साल प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का फैसला लिया है। लेकिन इस कार्टन की क्वालिटी बेहद खराब होने से सेब का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बागबान पैकेजिंग मैटेरियल 1 साल पहले जुटा लेता है ऐसे में बागबानों के पास अभी टेलीस्कोपिक कार्टन भी है। लिहाजा बागबानबाहर की फल मंडियों की तरफ़ पलायन कर रहे हैं। इसका सीधा नुकसान हिमाचल की फल मंडियों को हो रहा है। लिहाजा, सरकार को इस साल बागबानों को यूनिवर्सल कार्टन पर रिलैक्सेशन देना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने वामपंथी मित्रों के दबाव में आकार जल्दबाजी में यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का फैसला किया।

• जेल वार्डर की...

लिखित परीक्षा 28 जुलाई को

ऊना : कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में वार्डरों के 91 पदों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 28 जुलाई को होगी। जिला ऊना, कांगड़ा व चम्बा के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में दोपहर 12 बजे आयोजित होगी। इस परीक्षा केंद्र पर कुल 1149 अभ्यर्थी लिखित परीखा में बैठेंगे। इस बारे जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक एवं एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान ने बताया कि विभाग के महानिदेशक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थी अपने परीक्षा प्रवेश पत्र कारगार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग की वेबसाइट से या अपने पंजीकृत ई-मेल से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आरम्भ होने से दो घंटे पहले पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा हॉल में पेन, कार्डबोर्ड, एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र के अतिरिक्त कोई भी सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल, केलकुलेटर, इलैक्ट्रॉनिक घड़ी या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ बैग को परीक्षा हॉल में ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।

• शिमला में बरसे बादल...

प्रदेश के कई भागों में छह दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। उधर, बीती रात को प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण शिमला में जगह-जगह भूस्खलन हुआ है। आईएसबीटी टूटीकंडी के समीप पांजड़ी में भूस्खलन हुआ है। यहां चीड़ का एक पेड़ भी उखड़ गया। भूस्खलन से मार्ग बाधित रहा। वहीं बढ़श के समीप भारी बारिश के कारण पहाड़ी से गाड़ियों पर पत्थर गिर गए। इससे दो गाड़ियों को नुकसान हुआ है। नाग देवता मंदिर के पास भूस्खलन के कारण अनाडेल सड़क मार्ग बंद हो गया।